निर्यात वित्तपोषण के लिए सरकार का बड़ा कदम

पीयूष गोयल की बहु-स्तरीय बैठकों से औद्योगिक मजबूती को बढ़ावा

नई दिल्ली, 13 जुलाई.केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पिछले सप्ताह की प्रमुख गतिविधियों को साझा किया, जो भारत के व्यापार, औद्योगिक और बुनियादी ढांचे के परिदृश्य को मजबूत करने के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों को दर्शाती हैं.

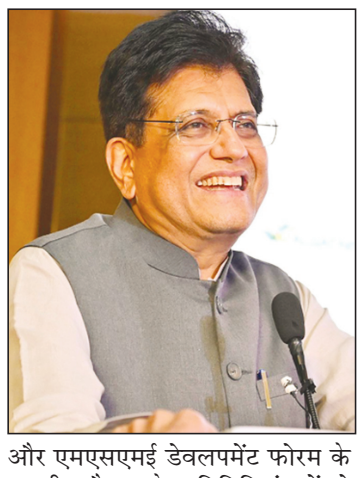

मंत्री ने भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष सहित अन्य प्रमुख बैंकों, ईसीजीसी लिमिटेड और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च-स्तरीय बैठक की. इस बैठक में निर्यात ऋण की स्थिति की समीक्षा की गई और भारत के निर्यात वित्तपोषण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के नए अवसरों पर चर्चा हुई.

श्रीनगर यात्रा के दौरान, गोयल ने कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और एमएसएमई डेवलपमेंट फोरम के कश्मीर चैप्टर के प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की. इस दौरान स्थानीय व्यवसायों को सशक्त बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया. उन्होंने जम्मू-कश्मीर फल और सब्जी प्रसंस्करण और एकीकृत कोल्ड चेन एसोसिएशन के हितधारकों के साथ भी बातचीत की, जिसमें क्षेत्र में कृषि-मूल्य श्रृंखलाओं की क्षमता पर ध्यान केंद्रित किया गया.

बेंगलुरु में, मंत्री ने देवनहल्ली में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) एयरोस्पेस विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में प्रमुख इकाइयों का दौरा किया. उन्होंने यूनिमेक एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड और सफ्रान एचएएल एयरक्राफ्ट इंजन प्राइवेट लिमिटेड का दौरा किया, जिसमें भारत की बढ़ती एयरोस्पेस विनिर्माण क्षमताओं और मेक इन इंडिया पहलों पर प्रकाश डाला गया.

> इसके अतिरिक्त, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप (पीएमजी) तंत्र के माध्यम से गुजरात और राजस्थान में प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने के लिए एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई. इसका उद्देश्य निष्पादन समय-सीमा में तेजी लाना और निवेश की बाधाओं को दूर करना है.ये सभी कार्य मंत्रालय के बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण को रेखांकित करते हैं, जिसका लक्ष्य औद्योगिक विकास, क्षेत्रीय विकास और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना है.

बायोगैस इकाइयों को मिलेगा नई ऊर्जा का बल

नयी दिल्ली, 13 जुलाई.भारतीय बायोगैस संघ (आईबीए) ने 50 लाख बायोगैस इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए परिवारों को 10,000 रुपये प्रति इकाई की सब्सिडी योजना की वकालत की है. आईबीए ने कहा कि ये इकाइयां मूल बुनियादी ढांचे के साथ तैयार हैं और इनसे ग्रामीण भारत में स्वच्छ ऊर्जा की स्वीकार्यता को व्यापक समर्थन मिल सकता है.भारतीय बायोगैस संघ के चेयरमैन गौरव केडिया ने कहा कि इस योजना पर कुल सरकारी खर्च 5,000 करोड़ रुपये होगा, जिसकी भरपाई दो साल में हो सकती है.उन्होंने बताया कि आईबीए ने सरकार से देशभर में 50 लाख बायोगैस इकाइयों को समर्थन देने के लिए एक साहसिक और दूरदर्शी कदम उठाने का आग्रह किया है.

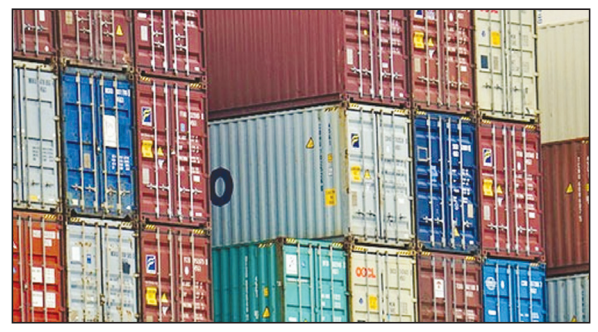

व्यापार घाटा जून में घटा : रिपोर्ट

तेल-सोना आयात में गिरावट से राहत मिली

जून में व्यापार घाटा घटकर 20.7 अरब डॉलर

नई दिल्ली, 13 जुलाई.यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) की एक रिपोर्ट के अनुसार, जून 2025 में भारत का व्यापार घाटा मामूली रूप से घटकर 20.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहने की संभावना है, जो मई के 21.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम है. कच्चे तेल की कीमतों में नरमी, सोने के आयात में कमी और सोर्सिंग रणनीति में बदलाव को इसका मुख्य कारण बताया गया है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि इजरायल-ईरान के बीच संघर्ष विराम के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में तेज लेकिन अस्थायी गिरावट, और ओपेक+ उत्पादन में वृद्धि ने भारत के तेल व्यापार संतुलन को बेहतर बनाने में मदद की. हालांकि जून में ब्रेंट क्रूड की कीमतें 64.01 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर औसतन 69.80 डॉलर प्रति बैरल हो गईं, लेकिन व्यापक आपूर्ति परिदृश्य ने आयात लागत में तेज वृद्धि को रोका.

भारत ने जून में 4.66 मिलियन बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल का आयात किया, जो मई के 4.72 mbpd से थोड़ा कम था. विशेष रूप से, भारतीय रिफाइनरियों ने रूस और अमेरिका से खरीद बढ़ा दी, जिससे मध्य पूर्व के पारंपरिक आपूर्तिकर्ताओं को पीछे छोड़ दिया गया. अकेले रूसी आयात दो साल के उच्च स्तर 2-2.2 mbpd पर पहुंच गया, जबकि 2025 के पहले चार महीनों में अमेरिकी तेल शिपमेंट में साल-दर-साल 270 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई. इस बदलाव ने रियायती रूसी कच्चे तेल और रणनीतिक विविधीकरण के कारण भू-राजनीतिक जोखिम को भी कम किया. हालांकि, जून में भारत के पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात में लगभग 10 प्रतिशत की गिरावट आई, जो 1.32 mbpd से घटकर 1.19 mbpd हो गया, जिससे समग्र व्यापार घाटे में सुधार की सीमा सीमित रही.

> देश का सोने का व्यापार घाटा भी जून में कम हो गया, क्योंकि बढ़ती अंतरराष्ट्रीय कीमतें, नियामक सख्ती और बढ़ते पुनर्चक्रण ने आयात पर अंकुश लगाया. जून में सोने की औसत कीमत 3,353 डॉलर प्रति औंस रही, जो महीने-दर-महीने 5 प्रतिशत और साल-दर-साल 32 प्रतिशत अधिक थी. सोने की घरेलू मांग भी सुस्त रही, मई में आयात 34.87 टन से घटकर 30.56 टन हो गया, और जून में इसके और गिरने की संभावना है.

फुटवियर क्षेत्र में विदेशी चमक

ताइवानी-वियतनामी कंपनियां भारत में करेंगी निवेश

नयी दिल्ली, 13 जुलाई.भारत के गैर-चमड़ा फुटवियर क्षेत्र में ताइवान और वियतनाम की कंपनियां निवेश करने को इच्छुक हैं. चमड़ा निर्यात परिषद (सीएलई) के चेयरमैन आर के जालान ने रविवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि इन देशों के निवेश को सुगम बनाने के लिए सरकारी समर्थन बेहद आवश्यक है.

जालान ने बताया कि ताइवानी और वियतनामी कंपनियां भारत में निवेश करना चाहती हैं, लेकिन उन्हें जूतों के सोल, सांचे, मशीनरी और कपड़े जैसे उत्पादों के आसान आयात के लिए समर्थन की आवश्यकता है. ये उत्पाद वर्तमान में वे चीन जैसे देशों से आयात करते हैं.

उन्होंने कहा कि देश का निर्यात अच्छी दर से बढ़ रहा है. परिषद 2025-26 में सात अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के निर्यात का लक्ष्य लेकर चल रही है. वित्त वर्ष 2024-25 में निर्यात 5.75 अरब डॉलर रहा था. भारतीय निर्यातकों के लिए अमेरिका 95.7 करोड़ डॉलर (लगभग 20 प्रतिशत हिस्सेदारी) के साथ शीर्ष गंतव्य रहा, जिसके बाद ब्रिटेन (11 प्रतिशत) और जर्मनी का स्थान है.

जालान ने उम्मीद जताई कि इस वर्ष निर्यात में लगभग 18 प्रतिशत की वृद्धि होगी. उन्होंने कहा कि देश में विनिर्माण को बढ़ावा देने से निर्यात और रोजगार सृजन को और प्रोत्साहन मिलेगा. अमेरिका के साथ व्यापार समझौते से अमेरिकी बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी.

एनसीएलएटी ने एनसीएलटी का आदेश ठुकराया

नयी दिल्ली, 13 जुलाई.राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने कर्ज में डूबी हिंदुस्तान नेशनल ग्लास इंडस्ट्रीज (एचएनजी) के समाधान पेशेवर को बदलने के राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के आदेश को खारिज कर दिया है. एनसीएलएटी की तीन सदस्यीय पीठ ने एनसीएलटी की कोलकाता पीठ को उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार एचएनजी के लिए बोलियों की मंजूरी पर फैसला करने की अनुमति दी है.एनसीएलएटी ने स्पष्ट किया कि न्यायिक प्राधिकरण उच्चतम न्यायालय के 16 मई, 2025 के निर्देशों के अनुसार योजना अनुमोदन आवेदन पर सुनवाई और फैसला कर सकता है.

वैश्विक अस्थिरता से शेयर बाजारों में गिरावट

भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता के संतुलन का इंतजार

टीसीएस के नतीजों ने मांग में सुस्ती दिखाई

नयी दिल्ली, 13 जुलाई (वार्ता) अंतरराष्ट्रीय व्यापार परिदृश्य और भू-राजनैतिक अनिश्चितताओं से प्रभावित कारोबार के कारण बीते सप्ताह भारतीय शेयर बाजारों में गिरावट तेज हो गयी.निवेशकों को अब भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता के संतुलित परिणाम की प्रतीक्षा है. वे फिलहाल किनारे रह कर कुछ चुनिंदा लिवाली करना बेहतर मान रहे हैं.

सप्ताह के दौरान तिमाही परिणामों का सीजन आईटी क्षेत्र की दिग्गज टीसीएस के पहली तिमाही के नतीजों से शुरू हुआ जिसमें बाजार को वैश्विक मांग में नरमी का संकेत दिखा है. सप्ताहांत यूरोपीय संघ और मैक्सिको के खिलाफ अमेरिका में 30 प्रतिशत आयात शुल्क लगाने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की घोषणा का इस सप्ताह बाजार पर नकारात्मक प्रभाव दिख सकता है.विश्लेषकों के अनुसार भारत में मुद्रास्फीति नीचे आने और ब्याज दर में नरमी से निवेशकों का बाजार में विश्वास बना हुआ है लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति की व्यापार नीति से व्याप्त अनिश्चिताओं और भू-राजनीतिक तनाओं के बीच मांग में कमी के कारण फिलहाल निवेश किनारे पर ही रहना बेहतर मान रहे हैं.

पिछले कुछ महीनों तक विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की ओर से अच्छे प्रवाह के बाद जुलाई में अब तक उनका निवेश कुल मिलाकर कम हुआ है. बजाज ब्रोकिंग रिसर्च के अनुसार स्थिर मैक्रो संकेतक और घटती मुद्रास्फीति तेजी की धारणा को बढ़ावा दे रही है, हालांकि वैश्विक संकेत अस्थिरता पैदा कर सकते हैं.

सावन मांग और वैश्विक सुधार से तेल महंगे

सरसों, मूंगफली, सोया और पाम तेल में तेजी, सोयाबीन की मांग कमजोर

नयी दिल्ली, 13 जुलाई.विदेशी बाजारों में खाद्य तेल कीमतों में सुधार और सावन के मौसम की बढ़ती मांग के कारण बीते सप्ताह घरेलू तेल-तिलहन बाजार में सरसों, मूंगफली तेल-तिलहन, सोयाबीन तेल, कच्चे पामतेल (सीपीओ) एवं पामोलीन तेल तथा बिनौला तेल के दाम में मजबूती दर्ज की गई.

हालांकि, ऊंचे भाव पर डी-आयल्ड केक (डीओसी) की कमजोर मांग के कारण सोयाबीन

तिलहन की कीमतें नुकसान के साथ बंद हुईं.

बाजार सूत्रों के अनुसार, विदेशी बाजारों में खाद्य तेलों के दाम में मजबूती और सावन में बढ़ती मांग ने अधिकांश खाद्य तेल-तिलहन में सुधार को प्रेरित किया. सरसों तेल-तिलहन में मजबूती का मुख्य कारण कच्ची घानी की बड़ी तेल मिलों की मांग और सावन की बढ़ी हुई खपत रही. सूत्रों ने सरकार को सलाह दी कि सरसों के मौजूदा स्टॉक को आगामी फसल आने तक (सात-आठ माह) सावधानी से बेचना होगा. यह स्टॉक स्टॉकिस्टों के बजाय सीधे पेराई मिलों को बेचा जाना चाहिए, जो पेराई के बाद तेल को बाजार में उतारने की गारंटी दें, ताकि जमाखोरी रोकी जा सके.

इलेक्ट्रॉनिक्स-फार्मा पर पीएलआई की मेहरबानी

नयी दिल्ली, 13 जुलाई.भारत की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना ने देश के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्युटिकल्स क्षेत्रों ने वित्त वर्ष 2024-25 में कुल वितरित प्रोत्साहन राशि का 70 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त किया है.

यह योजना 2021 में 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 14 क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी.

वित्त वर्ष 2024-25 में सरकार ने पीएलआई के तहत कुल 10,114 करोड़ रुपये वितरित किए हैं. आंकड़ों के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की पीएलआई कंपनियों को इसमें से सर्वाधिक 5,732 करोड़ रुपये की राशि मिली है, जबकि दवा क्षेत्र की कंपनियों को 2,328 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं. पिछले वित्त वर्ष में पीएलआई के तहत वितरण 9,721 करोड़ रुपये रहा था. ये आंकड़े इन क्षेत्रों में भारत की मजबूत विनिर्माण क्षमता और मूल्य वर्धित निर्यात को बढ़ावा देने के प्रयासों को दर्शाते हैं.

सितंबर से मर्सिडीज कारें होंगी महंगी

यूरो के मुकाबले रुपये की कमजोरी बनी चुनौती

नयी दिल्ली, 13 जुलाई.लक्जरी कार निर्माता मर्सिडीज बेंज इंडिया सितंबर से अपने वाहनों की कीमतों में एक से डेढ़ प्रतिशत तक की बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है. कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष अय्यर ने बताया कि यूरो के मुकाबले रुपये के कमजोर होने के कारण यह कदम उठाना पड़ रहा है.

मर्सिडीज बेंज इस साल पहले ही जनवरी और जुलाई में अपने वाहनों के दाम बढ़ा चुकी है, और यह तीसरी मूल्यवृद्धि होगी. अय्यर ने कहा, सितंबर में यूरो के कारण कीमतों में एक और बढ़ोतरी होने वाली है. पिछले एक महीने में यूरो 100 रुपये के स्तर पर बना हुआ है, और इसमें कोई बदलाव नहीं आया है.

समाचार विशेष

कम आबादी वाली जातियों और छोटी पार्टियों पर नजर

भाजपा का पासी समाज को साथ लेने के लिए खास प्लान

टना. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर भाजपा राज्य में कम आबादी वाली जातियों और छोटी पार्टियों के साथ मिलकर चुनावी रणनीति बना रही है. इसी क्रम में भाजपा के रणनीतिकारों ने शौर्य गाथा सह सम्मान समारोह आयोजित कर 'वीर शिरोमणि महाराजा बिजली पासी को न केवल याद किया बल्कि सच्चा हितैषी भी बताया.

बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वीर शिरोमणि महाराजा बिजली पासी को याद किया. उन्होंने कहा कि वर्ष 2000 में

भाजपा नीत अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने ही महाराजा बिजली पासी के नाम पर सामाजिक सम्मान के लिए एक डाक टिकट जारी करने का काम किया था. पासी समाज ने जीवन भर समाज को जोड़ने का काम किया. महाराजा बिजली पासी के सर्वस्व अर्पण करने वाली वीरता, पराक्रम और त्याग के प्रतीक को याद कर नव पीढ़ी की सीख लेनी चाहिए. फिर पासी समाज से वादा भी किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर नीरा की खेती को फिर से चालू करने का अधिकार देने का काम किया जाएगा.

नजर में एक प्रतिशत वोट बैंक!- भाजपा की नजर में पासी समाज का लगभग एक प्रतिशत वोट बैंक है. यह पासवान जाति से अलग जाति है. पर पासवान के नेता स्व रामविलास पासवान इसे साथ लेकर ही छह से सात प्रतिशत की राजनीति करते थे.

भाजपा की रणनीति

भाजपा छोटी छोटी जातियां को साधने की कोशिश लगातार कर रही है. गठबंधन की राजनीति से इतर भाजपा अपना साम्राज्य भी स्थापित करना चाहती है. लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने अपरोक्ष रूप से कुर्मी रैली का भी आयोजन कराया था. जातीय रैली या जाति विशेष नेताओं की जयंती और पुण्यतिथि के बहाने भी निशाना साधते रही है. पासी समाज को अपने प्रभाव में लेना भी इसी रणनीति का हिस्सा है.

निकाय चुनाव की तैयारी तेज करेगी भाजपा

रांची. राज्य में इस साल के अंत तक स्थानीय निकायों के चुनाव होने की संभावना है. भारतीय जनता पार्टी ने इसे लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं.

हालांकि, स्थानीय निकाय चुनाव दलगत आधार पर होंगे यह अभी स्पष्ट नहीं है. लेकिन चुनाव में अपने कार्यकर्ताओं की भागीदारी के लिए पार्टी ने वरिष्ठ नेताओं की कमेटी बनाकर सर्वेक्षण का काम प्रारंभ करने की योजना बनाई है. निकाय चुनाव के लिए बनी नेताओं की यह कमेटी जिलों का दौरा करेगी. संभावित उम्मीदवारों का नाम कार्यकर्ताओं से पूछने के बाद प्रदेश नेतृत्व को इससे अवगत कराया जाएगा. प्रदेश संगठन महामंत्री ने जुलाई महीने से पहले इस कमेटी के गठन और जिलों के दौरे की प्रक्रिया चलाने की सलाह दी है. निकाय चुनाव में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र के मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए भाजपा राज्य सरकार की नीतियों पर आंदोलनात्मक कार्यक्रम चलाने की योजना भी बना रही है.

3 करोड़ प्रवासी मतदाता बनेंगे किंगमेकर!

पटना. बिहार में विधानसभा चुनाव इस वर्ष दिवाली और छठ के आसपास होने की संभावना है. दिवाली और छठ के समय देश के विभिन्न हिस्सों में काम करने वाले प्रवासी श्रमिक वापस अपने गांव-शहरों में लौटते हैं. एक अनुमान के मुताबिक पूजा को लेकर करीब 3 करोड़ प्रवासी मतदाता बिहार वापस आते हैं.

इस दौरान चुनाव होने से बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक भी वोट डाल पाएंगे और चुनाव परिणाम तय करने में उनकी बड़ी भूमिका होगी. इसलिए सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने प्रवासी मतदाताओं को लुभाने की विशेष योजना पर काम कर दिया है.

बीजेपी भी प्रवासी मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रही है. पार्टी ने इन मतदाताओं तक पहुंचने के लिए एक खास योजना बनाई है. बीजेपी चाहती है कि ये मतदाता त्योहार मनाने के साथ-साथ वोट भी डालें. बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और दुष्यंत गौतम, और बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मिलकर इस योजना की रूपरेखा तैयार की थी. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बीजेपी लोगों से बिहार जाकर वोट करने की अपील कर रही है.

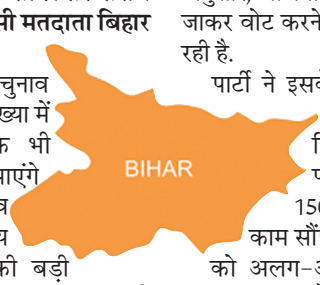

पार्टी ने इसके लिए देश के लगभग 150 जिलों को चुना है. पार्टी ने लगभग 150 नेताओं को यह काम सौंपा है. इन नेताओं को अलग-अलग जिलों में जाकर बिहार के प्रवासियों से मिलना है. बीजेपी ने पहले ही 28 राज्यों के लिए प्रभारियों को नियुक्त कर दिया है. दिलीप जायसवाल ने कहा कि बीजेपी को उम्मीद है कि वे प्रवासियों को वोट डालने के लिए समय पर वापस आने के लिए मना लेंगे.

प्रवासी श्रमिकों का पूरा डेटा तैयार

सूत्रों के अनुसार, अगला कदम प्रवासियों को कॉल करना और उनसे पूछना होगा कि क्या वे वोट डालने के लिए वापस आएंगे. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बीजेपी अपने नेताओं को एक 14-सूत्रीय सवालों की लिस्ट दे रही है. इसका शीर्षक है - 'आम बिहारी प्रवासियों की जानकारी'. इसमें नाम, फोन नंबर, पता, पेशा, सामाजिक वर्ग, विधानसभा क्षेत्र, मूल जिला और यह जानकारी शामिल है कि वह बीजेपी समर्थक है या नहीं और घर पर मतदाता का क्या प्रभाव है. इस जानकारी को इकट्ठा किया जा रहा है और अगस्त तक इसे एक ऐप पर अपलोड किया जाएगा.

विशेष | कौन बनेगा दोस्त या दुश्मन

चिराग के रवैये से राजग में असमंजस

नई दिल्ली. एनडीए के सहयोगी एवं केंद्र की मोदी सरकार में प्रमुख भूमिका में रहते हुए भी चिराग पासवान बार-बार बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं. बिहार की नीतीश कुमार सरकार की विधि-व्यवस्था पर भी प्रश्न खड़े कर रहे हैं. इसे विधानसभा चुनाव में राजग के लिए अच्छा नहीं माना जा रहा है. चिराग के इसी तेवर ने पिछले चुनाव में भी जदयू को बड़ा झटका दिया था.

इस बार फिर चिराग अभी तक राजग के घटक दलों से थोड़ा अलग रास्ते पर चलते दिख रहे हैं. इससे चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के कार्यकर्ताओं का उत्साह तो बढ़ रहा है, मगर राजग समर्थकों की दुविधा में भी वृद्धि हो रही है.

सवाल उठ रहे हैं कि आखिर चिराग के मन में क्या है. सियासी दोस्त कौन होगा और प्रतिद्वंद्वी कौन होगा. पांच वर्ष पहले भी चिराग खुद को नरेन्द्र मोदी का %हनुमान% बताते रहे थे और जदयू के हिस्से की सभी सीटों के साथ 144 सीटों पर प्रत्याशी भी उतार दिए थे. इस बार भी कुछ ऐसा ही संकेत दे रहे हैं. राजग के घटक दलों के दूसरी-तीसरी पंक्ति के नेताओं एवं समर्थकों के बीच इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति है कि चिराग का रुख गठबंधन की नीति के विपरीत होने जा रहा है या वह सिर्फ अपनी राजनीतिक हैसियत बढ़ाने की एक रणनीति पर काम कर रहे हैं.

चिराग अभी केंद्र सरकार में मंत्री हैं. लेकिन पुलिस व्यवस्था, रोजगार, भ्रष्टाचार एवं सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर बिहार की नीतीश सरकार की आलोचना करते हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से जदयू और भाजपा को असहज करता है.

पहले क्या थी रणनीति?

पिछले चुनाव में लोजपा ने जदयू का नुकसान तो बहुत किया लेकिन खुद एक ही सीट जीत पाई थी. 110 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई और सिर्फ एक सीट पर जीत मिली. बाद में उक्त विधायक भी जदयू के साथ हो लिया. शायद पूरी कवायद इसलिए भी है कि भविष्य में उन्हें मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में देखा जाए. राजग से अलग होकर लड़ना इस बार संभव नहीं है क्योंकि वह केंद्र में मंत्री भी हैं. जाहिर है, चिराग अपने सियासी चालों से बिहार की राजनीति को उलझन में डाल तो रहे हैं, लेकिन एनडीए में रहते हुए विरोध और बेबाकी का यह तरीका उन्हें चमका भी सकता है या अलग-थलग भी कर सकता है. यह इसपर भी निर्भर करेगा कि वह विरोध की अपनी शैली को आगे बढ़ाएंगे या फिर पुरानी सियासी प्रतिबद्धता के साथ एनडीए की भाषा बोलने लगेंगे.

राजनीतिक विश्लेषक अभय कुमार का मानना है कि चिराग को पता है कि महागठबंधन में उनके लिए सम्मानजनक जगह नहीं है. इसलिए राजग के साथ रहते हुए अपना कद बढ़ाने के प्रयास से पीछे नहीं हटने वाले हैं. अहमियत बढ़ेगी तो राजग में सीटें भी ज्यादा मिल सकती हैं.